(iii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY).

(iv) Employment Assurance Scheme (EAS).

(v) Indira Awaas Yojana (IAY).

(b) A statement showing the physical and financial achievements under these programmes during the last three years as also for the current year, State-wise, is given in Annexures [*See Appendix*, 176 *Annexure Nos.* (19) to (23)]

(c) and (d) No such case of diversion of funds from poverty alleviation programmes to other purposes has come to the notice of the Govt.

Low Level of Floor Price of Copra

*68. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the coconut cultivators of Kerala are aggrieved with the decision of the Central Government fixing the floor price of copra at a lower level;

(b) the criteria for fixing the floor prices for commodities;

(c) whether this criteria has been applied in the case of copra also;

(d) whether Government are likely to reconsider the request of State Government of Kerala to increase the floor price for copra; and

(e) whether Government are likely to fix the support price for coconut oil?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (DR. JAGANNATH MISHRA): (a) Yes, it has been reported that coconut cultivators are not satisfied with the Government decision on the Minimum Support Price of Copra for the 1996 Season.

(b) The Government decides on the Minimum Support Prices for various agricultural commodities taking into account the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), the views of the concerned State Governments and the Central Government Ministries as well as such other relevant factors which, in the opinion of the Government, are important for fixation of the support prices.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government announced the price policy for copra for 1996 season on 1.2.1996 after taking into account all the relevant factors including the opinion of the State Governments.

(e) The Government of India does not fix any support price for coconut oil.

आरक्षण-नीति के क्रियान्वयन में हुई प्रगति

*69. **श्री रामजीलाल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रत्येक आरक्षित वर्ग में भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार ने किन-किन राज्यों में अब तक अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत सीटें भरना शुरू नहीं किया है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने संविधान के हाल ही के संशोधन के अनुसार वर्ग-I के पदों पर पदोन्नति हेतु भी आरक्षण-नीति लागू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख): राज्यों से संबंधित आरक्षण नीति संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक राज्य में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध में समूह "क" के अन्तर्गत पदोन्नति में बशर्ते कि योग्यता हो, और समूह "क" के निम्नतम स्तर तक चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, समूह "क" में 5700/-रुपये तक वेतनमान वाले पदों के लिए उपलब्ध रियायत ऐसी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों को, जो काफी वरिष्ठ हैं और पदोन्नति के विचारार्थ क्षेत्र की संख्या के भीतर, जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, आते हैं, उस सूची में शामिल किया जाएगा बशर्ते उन्हें पदोन्नति की दृष्टि से अनुपयुक्त नहीं माना जाता हो।

(घ) केन्द्र सरकार के पास राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित जाति	अनु०ज०जा०	अन्य पि०वर्ग	कुल %
1.	आंध्र प्रदेश	15	6	25	40
2.	असम	7	10 मैदानी	5	32
			5 पहाड़ी		27
3.	अरूणाचल प्रदेश	—	80	—	80
4.	बिहार	14	10	26	50
5.	गोवा	15(A&B)	7.5	2	24.5
		2(C&D)			
6.	गुजरात	7	14	27	48
7.	हरियाणा	20	—	27	47
8.	हिमाचल प्रदेश	15(A&B)	7.5	10	32.5
		22(C&D)	7.5	10	39.5
9.	जम्मू तथा कश्मीर	8	—	2	10
10.	कर्नाटक	18	5	50	73
		(15)	(3)	(32)	(50)
11.	केरल	8	2	40	50
12.	मध्य प्रदेश	15(A&B)	18(A&B)	14	47
		16(C&D)	20(C&D)		50
13.	महाराष्ट्र	13	7 अनधिसूचित आदिवासी खानाबदोश आदिवासी अन्य पिछड़ा वर्ग = 19 विशेष पिछड़ी श्रेणी = 2		
14.	मणिपुर	2	31	—	33

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित जाति	अनु०ज०जा०	अन्य पि०वर्ग	कुल
15.	मेघालय	—	80	—	80
16.	मिजोरम	—	45	—	45
	6.9.95 बाहुल्य अनुसूचित जनजाति कोई आरक्षण नहीं				
17.	नागालैंड		10	—	10
			80		80
18.	उड़ीसा	15	23	27	65
19.	पंजाब	25	—	5	30
20.	राजस्थान	16	12	22	50
21.	सिक्किम	कोई आरक्षण नहीं		21	21
22.	तमिलनाडु	18	1	50	60
				30	पिछड़े
				20	अत्यधिक पिछड़े
23.	त्रिपुरा	16	31	—	47
24.	उत्तर प्रदेश	21	2	27	50
25.	पश्चिम बंगाल	22	6	5	33
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	15	7.5	—	22.5
2.	चण्डीगढ़	15	7.5	27	49.5
3.	दादर एवं नगर हवेली	2	43	5	50
4.	दिल्ली	15	7.5	27	49.5
5.	दमन और द्वीव	15	7.5	27	49.5
6.	लक्षद्वीप	15	7.5	—	22.5
7.	पांडिचेरी	15	7.5	27	49.5

Assistance to Rural Youth for Fisheries

*70. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount of assistance provided to Rural Educated Tribal Youths for fisheries in the country particularly in backward/rural/tribal areas of Tamil Nadu;

(b) the details of the schemes launched for fisheries in fresh and brackish water particularly in Tamil Nadu;

(c) the details of assistance provided during the last three years, state-wise;

(d) the guidelines fixed for providing assistance;

(e) the number and locations of Demonstration-cum-Training Centres functioning at present, State-wise;

(f) whether Government propose to open more such training centres in the country; and

(g) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL